डा. चंद्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; it is noted. Yes; it is a serious matter. Naqvi*ji*, kindly convey it to the Finance Minister and IT Minister.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी): उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो इश्यू उठाया है, वह एक गंभीर इश्यू है। इस इश्यू पर, जो पूरी digital technology है, यदि उसकी hacking और उससे संबंधित उनकी कोई और स्पेसिफिक जानकारी होगी, तो वह जानकारी हम लेंगे और inform भी करेंगे।

Alleged illegal construction by a Public Limited Company in Veraval, Gujarat causing environmental problems

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): उपसभापति जी, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे गुजरात राज्य के सोमनाथ क्षेत्र में एक Sulphuric acid, industry है। अभी हाल ही में उन्होंने एक illegal construction का काम शुरू किया था। हमने स्थानीय नगर पालिका से पूछा था कि क्या उन्होंने आपसे या गवर्नमेंट से कोई इसकी मंजूरी ले रखी है या नहीं ले रखी है? उन्होंने जैसे ही वहां का inspection किया, उसके दूसरे ही दिन उन फैक्टरी वालों ने construction तोड़ना चालू कर दिया।

सर, यह एक Sulphuric acid plant है। इसका जो Sulphuric acid water समुद्र में जाता है, उससे समुद्र में प्रदूषण होता है। समुद्र में एक मार्ग रेखा होती है, जिससे पता चलता है कि उन्हें कितने किलोमीटर के बाद समुद्र के मध्य में पानी की लाइन से लेकर जाना है। लेकिन वे लोग यह करते हैं कि वह पानी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे जो छोटे-छोटे मछुआरे हैं, जो वहां पर नज़दीक में, 9 nautical miles के अंदर fishing करते हैं, वे इससे सफ़र करते हैं। वहां से कोई मछली आती नहीं है। जितनी भी मछलियां, इस Sulphuric acid water के क्षेत्र से आती हैं, वे पूरी तरह से मर जाती हैं, जिसके कारण pollution का भी खतरा हो जाता है।

दूसरी बात, factory को अपने workers के लिए यह जो जमीन दी गई थी, उन्होंने वह जमीन workers से खाली कराकर वहां पर नई factory लगा दी है। मेरी आपके माध्यम से यह गुजारिश है कि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और एनवॉयरनमेंट मिनिस्ट्री इस बाबत जांच करे और इसमें दखल दे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Kanimozhi; not present.

Alleged murder of a tribal farmer leader in Chhattisgarh by land mafias

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): उपसभापति जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मुझे तीन दिन के बाद बोलने का मौका मिला है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देती हूं। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जलाल राठिया नाम का एक आदिवासी किसान नेता, जिसकी एक भू-माफिया द्वारा हत्या की गई, उसकी हत्या इसलिए हुई, क्योंकि वह प्रसिद्ध कुनकुरी जमीन घोटाले, जो 300 एकड़ कुनकुरी की जमीन थी, उसका चश्मदीद गवाह था और उसने अपनी पेशी लगाई थी। जब हाई कोर्ट की अंतिम सुनवाई नजदीक थी, तभी उसकी हत्या की

[श्रीमती छाया वर्मा]

गई। माननीय उपसभापति जी, सिर्फ उसकी हत्या ही नहीं की गई, बल्कि लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया और उसकी लाश को सीधे जला दिया गया। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ बहुत ही अत्याचार और अन्याय हो रहा है। आदिवासियों का पूरा छत्तीसगढ़ अंचल जल रहा है। वहां की सरकार स्थिति पर नियंत्रण करने में और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह फेल है। उपसभापति जी, छत्तीसगढ़ की आबादी ढाई करोड़ है। उसमें से 72 लाख आदिवासी वहां पर निवास करते हैं। इनका कोई मां-बाप नहीं है, उनके लिए कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। वहां के आदिवासी कहते हैं कि,

"मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर
हम कहां तक भागें, शीशों का मुकद्दर लेकर।"

माननीय उपभापति जी, वहां की आदिवासी महिलाओं का तो और भी बुरा हाल है। आए दिन वहां के भू-माफिया, वहां की पुलिस और वहां के नक्सली आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार, अन्याय और बलात्कार कर उनकी हत्या करके फेंक देते हैं। वहां कोई सुनवाई नहीं होती। वहां पर हर दिन एक निर्भया कांड हो रहा है, लेकिन वहां की सरकार आदिवासियों की रक्षा के लिए इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और तो और आठवीं क्लास में पढ़ने वाला एक विजलु नाम लड़का और उसका भाई, दोनों अपनी बुआ के घर गए थे, लेकिन उसे मुखबिर समझकर उसकी हत्या कर देते हैं और पुलिस उसमें कुछ नहीं करती। वहां पर शासन, प्रशासन मूक बने हुए हैं। आदिवासियों पर हो रही इन घटनाओं से पूरा अंचल जल रहा है। माननीय उपसभापति जी, मैं चाहती हूं कि उस जलाल राठिया की मौत की पूरी फोरेंसिक जांच हो और उसके परिवार को उचित न्याय मिले, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री महेंद्र सिंह माहरा (उत्तराखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All the names of the hon. Members, who have associated themselves with it, may be included.

Concern over poor condition of infant health care in Madhya Pradesh

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, the issue that I am raising is both sensitive as well as sad. This is about the Infant Mortality Rate. मैं मध्य प्रदेश से हूँ और in Madhya Pradesh, the Infant Mortality Rate is amongst the highest in the country. हमारी चार-पांच स्टेट्स को बीमारू बोला जाता था। The term BIMARU was coined by Ashish, a demographer, way back in 1980. Forty per cent of India's population is affected by high rates of Infant Mortality.

Talking of Madhya Pradesh, in rural areas, the mortality rate is 57 per 1000 and, in urban areas, it is 35 per 1000. Sir, 73 per cent of Madhya Pradesh lives in rural areas. The national average of the Infant Mortality Rate is 39; our average is 52. In urban areas, this average is 35 per 1,000 and the national average is 26 per 1,000. The Maternal Mortality Rate in Madhya Pradesh, in 2012-13, was 221, when the national average was 167. Sir, 50 per cent of our posts of Gynecologists and Pediatricians are vacant. Out of 632 posts, 339 are vacant. दुख की बात तो यह है कि when States like Kerala, Goa, Manipur, Tamil Nadu and Maharashtra have achieved a national average of five, which is as good as the national average of US, Iran, Indonesia, Azerbaijan and Brazil, Madhya Pradesh still continues to lag behind. Our rate is worse than even that of Rwanda, which has an Infant Mortality Rate of 33, Ethiopia, which has 43, Zambia, which has 45. We are being compared with Somalia, Mauritania, which has 65, Burkina Faso, which has 61 and Afghanistan, which has 66.

The point that I am making is, इस देश में अगर हम सबके विकास की बात करते हैं, तो इन बच्चों के विकास के बारे में क्यों नहीं सोच सकते in a very progressive and proactive manner? क्योंकि हमारा आज भी मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है, it is a matter of great concern not only for us but for the entire country. That's all I want to say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. This is an important issue.